Ram Bhihari et al. International Journal of Recent Research Aspects ISSN: 2349-7688, Vol. 4, Issue 2, June 2017, pp. 82-88

पूर्वांचल में नक्सलवाद का उद्‌भव एवं प्रसार : मीरजापुर एवं सोनभद्र जनपद के सन्दर्भ में एक समीक्षात्मक विश्लेषण

राम बिहारी[1], डॉ० सी० एस० सूद[2]

[1]शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, हे० न० ब० गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल, उत्तराखण्ड

[2]प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, हे० न० ब० गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल, उत्तराखण्ड

वर्तमान में देश की सुरक्षा के समक्ष सबसे बड़ी चुनौति के रूप में सामने आया नक्सलवाद निरन्तर हिंसक व प्रभावी होता जा रहा है। देश का लगभग तीन चौथाई भाग नक्सलवाद की समस्या से पीड़ित है। आधी सदी से भी अधिक समय व्यतीत हो जाने पर भी इस समस्या का समाधान न हो पाना एक गंभीर चिंता का विषय है। नक्सलवाद का प्रसार मुख्यतः देश के पिछड़े व निर्धनताग्रस्त भागों में ही हुआ है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक पिछड़े हुए क्षेत्र पूर्वांचल में नक्सलवाद अपनी गहरी जड़े जमाने में सफल रहा है। वर्तमान शोध पत्र में पूर्वांचल में नक्सलवाद के उद्‌भव एवं प्रसार का मीरजापुर एवं सोनभद्र जनपद के सन्दर्भ में एक समीक्षात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है।

सूचक शब्द : प्रसार– फैलाव या विस्तार, अभिप्रेरक– प्रभावित करने वाले कारक

पूर्वांचल उत्तर मध्य भारत का एक भौगोलिक क्षेत्र है, जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर पर स्थित है। यह उत्तर में नेपाल, पूर्व में बिहार, दक्षिण पूर्व में झारखण्ड, दक्षिण में छत्तीसगढ़, दक्षिण पश्चिम में मध्य प्रदेश के बघेलखण्ड क्षेत्र तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र से लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश को विभाजित कर पृथक पूर्वांचल राज्य बनाने की माँग लम्बे समय से की जा रही है। पूर्वांचल मूलतः भोजपुरी भाषी क्षेत्र है तथा प्रारम्भ में पूर्वांचल राज्य की कल्पना पूर्वी उत्तर प्रदेश के 17 भोजपुरी भाषी जिलों को मिलाकर की गयी[1], किन्तु इस सन्दर्भ में एक माँग यह भी है कि उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भोजपुरी भाषी जिलों को मिलाकर पूर्वांचल राज्य का गठन किया जाय। वर्ष 2011 में पूर्वांचल राज्य आन्दोलन' (पीआरजे) द्वारा प्रस्तावित पूर्वांचल राज्य में उत्तर प्रदेश के 8 मण्डल – वाराणसी, इलाहाबाद, विन्ध्याचल, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, फैजाबाद व देवीपाटन के 26 जिले यथा–वाराणसी, चन्दौली, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महराजगंज, बस्ती, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, अकबरपुर, सुल्तानपुर, अमेठी, मीरजापुर, भदोही व सोनभद्र शामिल हैं।

यदि पीआरजे द्वारा परिकल्पित पूर्वांचल राज्य का गठन किया गया तो लगभग 79807 वर्ग कि०मी० में विस्तृत यह देश का सोलहवां विशालतम राज्य होगा तथा इसकी जनसंख्या लगभग 7.52 करोड़ होगी। इसका जनसंख्या घनत्व 943 तथा लिंगानुपात 965 होगा। पूर्वांचल राज्य के रूप में कल्पित यह समस्त क्षेत्र अल्पविकसित व निर्धनताग्रस्त है। इस क्षेत्र में लगभग 4 करोड़ व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं तथा डेढ़ करोड़ से भी अधिक नौजवान बेरोजगार हैं।[2]

पूर्वांचल में नक्सलवाद का उद्‌भव एवं प्रसार

उत्तर प्रदेश में नक्सलवादी आन्दोलन का उद्भव 1969–70 में स्वर्गीय श्री चन्द्रभान गुप्ता के मुख्यमंत्रीत्वकाल में ही हो गया था। वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से आदिवासियों एवं जमींदारों के मध्य भूमि विवाद से प्रारम्भ यह संघर्ष मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के चारू मजूमदार, कानू सन्याल व जंगल संथाल का नेतृत्व प्राप्त होते ही देश के अन्य भागों में तेजी से फैल गया। दक्षिण में आन्ध्र के श्रीकाकुलम से उत्तर में बिहार के मुसहरी व भोजपुर के साथ ही उत्तर प्रदेश के तराई में स्थित लखीमपुर के पलिया में इस आन्दोलन का व्यापक प्रभाव पड़ा। वर्ष 1969–70 के दौर मे नक्सली गतिविधियों का प्रभाव उत्तर प्रदेश में पलिया के अतिरिक्त पहाड़ी क्षेत्रों में भी रहा जो अब उत्तराखण्ड राज्य का हिस्सा हैं, किन्तु तत्कालीन नक्सलवादी आन्दोलन का प्रभाव इन क्षेत्रों में अधिक दिनों तक नहीं रहा।

वर्तमान समय में नक्सलवाद ने पूर्वांचल कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। सोनभद्र, मीरजापुर तथा चंदौली जनपद इस क्षेत्र में नक्सलियों के प्रमुख गढ़ बन गये हैं। पूर्वांचल में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के उपरान्त बुन्देलखण्ड व अवध में भी नक्सलियों ने दस्तक दी है। सरकार का मानना है कि प्रदेश के 18 जिलों में नक्सलियों का जाल फैल चुका है। एस० टी० एफ० व गुप्तचर विभाग के अधिकारियों का अभिमत है कि चंदौली के नौगढ़ क्षेत्र से नक्सली आंतक ने प्रदेश में प्रवेश कर सोनभद्र एवं मीरजापुर के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों को अपना गढ़ बनाया है। इन जनपदों में अपनी स्थिति मजबूत करने के पश्चात् गाजीपुर, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, चित्रकूट, इलाहाबाद, बांदा व फर्रूखाबाद में इन्होंने अपना प्रसार किया। नेपाल से लगे सात सीमावर्ती जनपदों यथा– महारागंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी तथा पीलीभीत में भी नक्सलियों के मजबूत नेटवर्क कायम होने के प्रमाण मिले हैं। इलाहाबाद में 7 फरवरी 2010 को सीमा आजाद व विश्व विजय उर्फ कमल की गिरफ्तारी से नक्सलियों के कानपुर में होने का प्रमाण मिला। एस० टी० एफ० ने 8 फरवरी 2010 को कानपुर से उ० प्र०, बिहार, उत्तराखण्ड के कथाकथित भावी प्रभारी व चिंतक बंशीधर व पोलित ब्यूरो के पूर्व सदस्य बलराज सहित 8 माओवादियों को गिरफ्तार किया। इन्होंने एस० टी० एफ० टीम को बताया कि कानपुर में लाल आन्दोलन की नींव तैयार करने में शहर के अनेक उद्योगपति व ठेकेदार माओवादियों को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं।[3]

पूर्वी उत्तर प्रदेश के मीरजापुर, सोनभद्र तथा चंदौली जनपद में नक्सलियों का प्रभाव अधिक है। इन जनपदों की भौगोलिक परिस्थितियाँ पूर्वांचल में गतिविधियों को संचालित करने के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराती हैं। सोनभद्र में 273, चंदौली में 241, गाजीपुर में 30, मीरजापुर में 107, मऊ में 02, बलिया में 53, देवरिया में 24 तथा कुशीनगर में 01 गाँव नक्सलवाद से प्रभावित हैं।[3] पूर्वांचल देश के सर्वाधिक पिछड़े हुए क्षेत्रों में से है। यहाँ की सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों में विद्यमान असमानता ने नक्सलियों को अपना प्रभाव क्षेत्र स्थापित करने का अवसर प्रदान किया है।[4]

मीरजापुर एवं सोनभद्र का परिचयात्मक अध्ययन

पूर्वांचल के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित मीरजापुर एवं सोनभद्र जनपद दक्षिण पूर्व में स्थित उत्तर प्रदेश के सीमान्त जनपद हैं, जिनकी सीमा आपस में परस्पर लगी हुई है। मीरजापुर जनपद की सीमा

© 2017 IJRRA All Rights Reserved

दक्षिण पश्चिम में मध्य प्रदेश की सीमा से लगी हुई है तथा सोनभद्र की सीमा दक्षिण पश्चिम में मध्य प्रदेश, दक्षिण में छत्तीसगढ़, दक्षिण पूर्व में झारखण्ड तथा पूर्व में बिहार राज्य की सीमा से लगी हुई है। सोनभद्र पूर्व में मीरजापुर जनपद का दक्षिणी भाग था जिसके अन्तर्गत राबर्ट्सगंज तथा दुद्धी तहसीलें सम्मिलित थीं। इन दोनों तहसीलों को मिलाकर 4 मार्च 1989 को सोनभद्र नाम से एक नये जनपद का गठन किया गया। संयुक्त मीरजापुर जनपद स्वयं पूर्व में वाराणसी जनपद का भाग था जो 1930 में एक पृथक जनपद के रूप में अस्तित्व में आया। मीरजापुर जनपद के दक्षिणी भाग व सोनभद्र में अत्यधिक समानता है। दोनों ही भागों में वन एवं पहाड़ों की अधिकता है तथा यहाँ की भूमि उबड़–खाबड़ व पथरीली है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मीरजापुर जनपद की जनसंख्या 2496970 तथा सोनभद्र की जनसंख्या 1862559 है। दोनों जनपदों का एक संक्षिप्त परिचय तालिका 1 में प्रस्तुत है–

तालिका 1 : मीरजापुर एवं सोनभद्र जनपद का एक संक्षिप्त परिचय

क्र. सं.	विवरण	जनपद मीरजापुर	जनपद सोनभद्र
1.	क्षेत्रफल	4521 वर्ग किमी	6788 वर्ग किमी
2.	वन क्षेत्रफल (वर्ष 2014–15)	24.2 %	47.8 %
3.	कृषि (बोया गया क्षे०,वर्ष 2014–15)	46.5 %	23.7 %
4.	सिंचित क्षेत्रफल (वर्ष 2014–15)	72.6 %	29.3 %
5.	समस्त जोतों में लघु एवं सीमान्त जोतों की संख्या (प्रतिशत)	91.2 %	83.3 %
6.	समस्त जोतों में लघु एवं सीमान्त जोतों का क्षेत्रफल (प्रतिशत)	57.0%	38.1%
7.	सीमान्त जोतों का औसत आकार (हेक्टे०)	0.4	0.4
8.	समस्त जोतों का औसत आकार (हेक्टे०)	0.88	1.23
9.	जनसंख्या	2496970	1862559
10.	पुरूष	1312467 (52.56%)	971344 (52.15%)
11.	महिला	1184503 (47.44%)	891215 (48.85%)
12.	अनु० जाति	661033 (26.48%)	421661 (22.64%
13.	अनु० जनजाति	20226 (0.81%)	385018 (20.67%
14.	लिंगानुपात	903	918
15.	जनसंख्या घनत्व	552	274
16.	साक्षरता दर	68.5%	64.0%
17.	मुख्य कर्मकारों में कृषक	26.6%	25.6%
18.	मुख्य कर्मकारों में कृषक श्रमिक	28.1%	37.1%
19.	मुख्य कर्मकारों में परिवारिक उद्योग	8.4%	3.7%
20.	मुख्य कर्मकारों में अन्य कर्मकार	36.9%	33.6%

स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका, 2016, मण्डल विन्ध्याचल, तालिका संख्या 2.

मीरजापुर एवं सोनभद्र में नक्सलवाद की चुनौती

© 2017 IJRRA All Rights Reserved

मीरजापुर एवं सोनभद्र की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों एवं पिछड़ेपन का लाभ उठाकर 90 के दशक में नक्सलियों ने यहाँ अपनी गतिविधियाँ प्रारम्भ की। उ० प्र० पुलिस द्वारा वर्ष 1997 को प्रदेश में नक्सल गतिविधियों के प्रारम्भ का अधिकारिक वर्ष माना गया है।[5] इस वर्ष के बाद जनपद सोनभद्र एवं मीरजापुर में नक्सलियों ने एक के बाद एक कई घटनाओं को अंजाम दिया और उनकी सक्रियता लगातार बढ़ती गयी। वर्ष 2001 में घटित भवानीपुर मुठभेड़ इस दिशा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का कारक बनी। इस मुठभेड़ की प्रतिक्रिया स्वरूप नक्सली घटनाओं में व्यापक वृद्धि हुई। 9 मार्च 2001 की रात्रि में मीरजापुर जनपद के मड़िहान पुलिस स्टेशन के सुदूर गाँव भवानीपुर में पुलिस ने एक 14 वर्षीय बालक सहित 16 व्यक्तिों को नक्सली बताकर मुठभेड़ में मार गिराया। मुठभेड़ में मारे गये लगभग सभी व्यक्ति दलित एवं आदिवासी समुदाय से थे। इस घटना के उपरान्त तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने इस अभियान में शामिल पुलिस कर्मियों को बहादुरी का प्रशस्त्रि पत्र प्रदान किया।[6] किन्तु, घटना की परिस्थितियाँ पुलिस के दावों से मेल नहीं खा रही थीं। स्थानीयजन, पत्रकार व मानवाधिकार संगठनों ने इस मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए जाँच की माँग की। उच्चतम न्यायालय के निदेश पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जाँच की गयी। पुलिस ने जिन नक्सलियों के मारे जाने का उल्लेख किया था उसमें से सुरेश बियार भवानीपुर मुटभेड़ के एक सप्ताह पश्चात् मीरजापुर कहचरी में आयोजित विरोध सभा में उपस्थिति होकर जीवित होने का प्रमाण प्रस्तुत कर पुलिस के दावों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। इसके बाद लालव्रत कोल व देवव्रत कोल ने भी सामने आकर स्वयं के जीवित होने का प्रमाण दिया। इनके सामने आने पर यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि फिर पुलिस द्वारा मागे व्यक्ति कौन थे। निरन्तर बढ़ती माँग के मद्देनजर सरकार ने इस मुठभेड़ की सीबीआई से जाँच का आदेश दिया, परन्तु डेढ दशक से भी अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी सीबीआई द्वारा की जा रही जाँच का किसी निष्कर्ष पर न पहुँचना अत्यधिक दुःखद है।[7] पूर्वांचल में नक्सलवाद के बढ़ते प्रभाव पर नियंत्रण हेतु तत्कालीन केन्द्र की भाजपा सरकार द्वारा 1,600 करोड़ रूपये के 'कर्मनाश' पैकेज की घोषणा की गयी।[8]भवानीपुर काण्ड के कुछ ही समय पश्चात् 22 नवम्बर 2001 को नक्सलियों ने मीरजापुर के खोराड़ीह में स्थित पीएसी कैम्प से 14 एस. एल. आर., एक स्टेनगन व 1400 कारतूस लूट लिया।[9] इस घटना में सीपीआई (एमएल) के कार्यकर्ताओं व उनके समर्थकों की भूमिका संदेहास्पद रही। पूर्वाचल में वर्ष 2004 में एक बड़ी घटना को अंजाम देते हुए नक्सलियों ने चंदौली के नौगढ़ में बारूदी सुरंग से विस्फोट कर पुलिस व पीएसी के 17 जवानों को मौत के घाट उतार दिया।[10] मीरजापुर एवं सोनभद्र जनपद में नक्सलियों द्वारा की गयी हत्याओं का विवरण तालिका 2 में प्रदर्शित है–

तालिका 2 : नक्सली घटनाओं में मारे गये व्यक्ति

क्र. सं.	घटना का वर्ष	जनपद मीरजापुर	जनपद सोनभद्र
1.	1997	— —	01
2.	1998	01	— —
3.	1999	02	— —
4.	2000	01	02
5.	2001	01	02
6.	2002	— —	02
7.	2003	03	03
8.	2004	02	06
9.	2005	— —	01
10.	2006	— —	03
11.	2007	— —	03
12.	2009	— —	02
योग		10	25

स्रोत : 1. कार्यालय पुलिस अधीक्षक मीरजापुर, पत्र सं० : ज० सू० अ० –66/2016, 25 फरवरी, 2016.
2. कार्लाय पुलिस अधीक्षक सोनभद्र, पत्र सं० प– 300/2005, 26 अक्टूबर, 2016.

© 2017 IJRRA All Rights Reserved

तालिका 2 से दृष्टव्य है कि विगत दो दशक में दोनों जनपदों में कुल 35 व्यक्तियों की नक्सलियों द्वारा हत्या की गयी। हत्या के अतिरिक्त नक्सलियों द्वारा लूट, आगजनी तथा हमला कर घायल करने की भी अनेक घटनायें की गयी। नक्सली हिंसा की गम्भीरता को देखते हुए प्रशासन द्वारा की गयी नक्सलरोधी कार्यवाही में बड़ी संख्या में नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है तथा अनेक मारे भी गये हैं। पुलिस कार्यवाही में गिरफ्तार एवं मारे गये नक्सलियों का विवरण तालिका 3 में प्रदर्शित है–

तालिका 3 : पुलिस कार्यवाही में गिरफ्तार एवं मारे गये नक्सलियों की संख्या

क्र. सं.	वर्ष	पुलिस द्वारा मारे गये नक्सली		पुलिस द्वारा गिफ्तार नक्सली	
		जनपद मीरजापुर	जनपद सोनभद्र	जनपद मीरजापुर	जनपद सोनभद्र
1.	1997	— —	— —	— —	01
2.	1998	— —	— —	— —	08
3.	1999	— —	— —	— —	02
4.	2000	— —	02	04	01
5.	2001	15	05	02	07
6.	2002	— —	07	08	24
7.	2003	01	02	03	26
8.	2004	— —	— —	01	15
9.	2005	— —	03	03	43
10.	2006	— —	02	05	22
11.	2007	— —	— —	02	07
12.	2008	— —	01	02	26
13.	2009	— —	01	02	18
14.	2010	— —	— —	— —	09
15.	2011	— —	— —	— —	11
16.	2012	— —	— —	— —	05
17.	2013	— —	— —	— —	04
योग		16	23	32	229

स्रोत : 1. कार्यालय पुलिस अधीक्षक मीरजापुर, पत्र सं० :ज० सू० अ० – 66/2016, 25 फरवरी, 2016.
2. कार्लय पुलिस अधीक्षक सोनभद्र, पत्र संख्या : प– 300/2005, 26 अक्टूबर, 2016.

पूर्वांचल में नक्सलवाद के प्रसार के अभिप्रेरक

पूर्वांचल में मुख्यतः एमसीसी, पीपुल्स वार ग्रुप तथा सीपीआई (एमएल) लिबरेशन जैसे नक्सली संगठनों के सक्रिय होने की जानकारी प्रकाश में आयी है। मीरजापुर, सोनभद्र तथा चंदौली में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए नक्सलियों द्वारा सोन–विन्ध्य–गंगा जोन कमेटी व नौगढ़–विजयगढ़ एरिया कमेटी के साथ ही कई अन्य लघु समितियों का भी गठन किया गया है। मीरजापुर एवं सोनभद्र जनपद की भौगोलिक, सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियाँ नक्सल प्रभावित पड़ोसी राज्यों की सीमावर्ती क्षेत्रों से अत्यधिक समानता रखती हैं तथा इस समानता ने यहाँ नक्सलवाद के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निर्धनता, अशिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क एवं संचार सेवाओं की दुर्बल स्थिति, नगण्य मजदूरी, ठेकेदारों एवं जमींदारों द्वारा शोषण, जनजातीय समाज की उपेक्षा तथा वन भूमि सम्बन्धी विवाद ऐसे प्रमुख कारण हैं जों नक्सलवादियों को अपना प्रभाव क्षेत्र स्थापित करने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध कराते हैं। इन दानों ही जनपदों में वंचना व गरीबी का साम्राज्य विद्यमान है। वर्ष 2002 में की गयी गणना के तहत मीरजापुर में 213658 (68.81%) तथा सोनभद्र में 150728 (64. 97%) परिवार ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते पाये गये जिसमें सर्वाधिक संख्या अनु०

© 2017 IJRRA All Rights Reserved

जातियों, अनु० जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों की रही।[11] जनपद मीरजापुर के नक्सल प्रभावित दक्षिणी भाग एवं सोनभद्र के नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में जनजातियों व दलितों की संख्या सर्वाधिक है और इनके पास रोजगार के साधनों का अभाव है। जनपद में स्थित खनन कम्पनियों एवं अन्य परियोजनाओं सहित बड़े शहरों में काम दिलाने के बदले बिचौलिये इनसे सुविधा शुल्क वसूल करते हैं। एक तरफ जहाँ इन्हें कम मजदरी पर काम करना पड़ता है वहीं बिचौलिये मोटी रकम कमाते हैं। शिक्षा व जानकारी के अभाव में ये सरकार द्वारा चलायी जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का भी समुचित लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तालिका 1 से स्पष्ट है कि दोनों ही जनपदों में कृषि भूमि की स्थिति अच्छी नहीं है। यद्यपि इस दृष्टि से मीरजापुर जनपद की स्थिति बेहतर है जहाँ 46.5 प्रतिशत भू–भाग पर कृषि कार्य किया जा रहा है जबकि सोनभद्र में मात्र 23.7 प्रतिशत भू–भाग पर ही कृषि कार्य सम्पादित हो पा रहा है। पुनः लघु एवं सीमान्त जोतों की संख्या अधिक है जबकि उनका क्षेत्रफल कम है जबकि दोनों ही जनपदों में कृषि पर निर्भर कर्मकारों की संख्या सर्वाधिक है। इस तरह कृषि जोतों के औसत आकार, कृषि भूमि के असमान वितरण तथा सिंचाई सुविधाओं के अभाव व अनुपजाऊ भूमि की अधिकता के चलते कृषि से जीवन यापन करना अधिकांश के लिए एक कठिन चुनौती है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में वामपंथी हिंसा के प्रसार में भूमि सम्बन्धी अनियमितता एक प्रमुख कारक है। उल्लेखनीय है कि सोनभद्र, मीरजापुर तथा चंदौली जनपद को मिलाकर लगभग 54,000 एकड़ भूमि या तो विवादित है या अवैध कब्जों की गिरफ्त में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2002 में इसके निस्तारण के लिए जिलाधिकारी/उपायुक्त की अध्यक्षता में संरक्षण कमेटियों का गठन किया था, किन्तु इन कमेटियों ने किसी भी मामले की सुनवाई नहीं की।[12] सोनभद्र जनपद में जमीन के हक को लेकर आदिवासियों के आन्दोलन में आयी तेजी के साथ ही कथाकथित नक्सलवादी आन्दोलन की चर्चा भी प्रारम्भ हो गयी है। पुलिस प्रशासन द्वारा आन्दोलन में आयी तेजी को नक्सलवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। उनका मानना है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं के भड़काने पर स्थानीय जनता उग्र होकर वन भूमि पर कब्जा कर लेती है जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाती है और नक्सलियों को सक्रिय होने का अवसर मिल जाता है। अनेक लोगों का मानना है कि इस आन्दोलन को नक्सलवाद से जोड़ने पर स्थानीय प्रशासन को लाभ होता है, क्योंकि नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र साबित करने पर केन्द्र व राज्य की सरकारें नक्सलवाद के नियंत्रण हेतु स्थानीय प्रशासन को मोटी धनराशि उपलब्ध कराती हैं।[13]

मीरजापुर एवं सोनभद्र में बड़ी संख्या में बाहरी व्यक्तियों ने आकर राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत तथा स्थानीय जनता की गरीबी व निर्धनता का फायठा उठाकर जमीनों अधिकार कर लिया है। सोनभद्र में जमीन के मुद्दे पर चलने वाले आन्दोलन में तेजी आयी है, तो उसके पीछे कुछ ठोस कारण हैं, जिन्हें समझे बिना यहाँ के दलित आदिवासी संघर्ष पर कोई टिप्पणी करना अनुचित होगा। उल्लेखनीय है कि देश के अधिकांश वन क्षेत्र एवं सीमावर्ती भागों में स्थानीय पुलिस–प्रशासन, वन विभाग व स्थानीय दबंग समुदायों की मिलीभगत से भूमि सम्बन्धी गडबड़ियाँ व्यापक स्तर हुई हैं तथा इन क्षेत्रों में भूमिहीनों द्वारा लगातार आन्दोलन भी चलाये जाते रहे हैं। जब–जब सरकारों ने इन आन्दोलनों के प्रति दमनात्मक कार्यवाही की है, तब–तब ये जनवादी आन्दोलन भी हिसंक रूप में परिणिति हुए हैं। मीरजापुर, सोनभद्र तथा चंदौली में स्वतंत्रता के इतने वर्ष व्यतीत होने के बाद भी जमीनों का बन्दोबस्त न होना, खनिज संपदा के अकूत भंडार पर भू एवं खनन माफियों का बढ़ता एकाधिकार, सदियों से हाशिये पर रहे आदिवासी समुदायों के संवैधानिक अधिकारों का हनन तथा लोगों की बढ़ती राजनीतिक चेतना आन्दोलन में आयी तेजी के प्रमुख कारण हैं।[14]

स्पष्ट है कि पूर्वांचल में नक्सलवाद के प्रसार की जड़ें इन जनपदों की सामाजिक–आर्थिक व भौगोलिक परिस्थितियों से पोषित हैं। सर्वविदित है कि देश में भूमि सुधार कानूनों की असफलता ने नक्सलवाद को जन्म दिया। यद्यपि सरकार ने स्वतंत्रता पश्चात् जमींदारी प्रथा को समाप्त कर भूमि पुनर्वितरण सम्बन्धी कानून भी बनाया तथापि इसके क्रियान्वयन में व्यापक अनियमिततायें की गयी। मीरजापुर व सोनभद्र के वन क्षेत्र में जमीन के फर्जी पट्टे, बन्दोबस्त सम्बन्धी धांधली, अवैध खनन, बड़ी कम्पनियों को खनन का अधिकार पत्र, खदानों व तेंदू पत्ते की तुड़ाई तथा कृषि कार्य में न्यूनतम मजदूरी से भी कम भुगतान, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कारण स्थानीय आदिवासियों का विस्थापन इत्यादि नक्सलवादी समस्या के मूल कारण के रूप में

© 2017 IJRRA All Rights Reserved

सामने आये हैं। अतः इन समस्याओं को हल किये बिना नक्सलवाद के प्रसार को नियंत्रित करना सहज संभव प्रतीत नहीं होता। अस्तु नक्सलवाद के उन्मूलन हेतु इन समस्याओं का समाधान अपरिहार्य है।

सन्दर्भ सूची

---

1 सिंह, इन्देव : ''पूर्वांचल एक नजर मे'', http://hindivivek.org/

2 सागर, एम. अफसर खां, ''मांग अलग पूर्वांचल राज्य की'', http://www.pravakta.com/demand-of- seperate-poorvanchal- state/

3 गुप्त, परशुराम (2012), नक्सल विद्रोहः समस्या एवं समाधान, बरेली : प्रकाश बुक डिपो, पृ. 37—38.

4 तदैव, पृ० 37.

5 The Times of India, " States meet to discuss Maoist menance", Varanasi, 18 March, 2008, p. 3.

6 Report on Encounter at Bhavanipur, (April 2001), " Dead. Hence Gulty. ' Encounter' at Bhavanipur and itsAftermath", Peoples Union for Democratic Rights, Delhi, , p. 14.

7 http://lalkona.blogspot.in/2010/12/blog-post.html 4/

8 Report on Encounter at Bhavanipur, (April 2001), " Dead. Hence Gulty. ' Encounter' at Bhavanipur and itsAftermath", Peoples Union for Democratic Rights, Delhi, p. 14.

9 मिश्रा, एस. के. (2010), नक्सलवाद, नई दिल्ली : के. डब्ल्यू. पब्लिशर, पृ. 272,

10 Singh, Prakash (2011), The Naxalite Movement in India, New Delhi : Rupa Publication, p. 181.

11 http://rd.up.nic.in/bpl2002.htm 1/

12 मिश्रा, एस. के. (2010), पूर्वोक्त, पृ. 272.

13 तदैव, पृ. 271.

14 तदैव, पृ. 273—274.

IJRRA